नईदुनिया

नेपाल : बाढ़ में लापता 4,655 लोग अगर 3 माह तक नहीं मिले तो मृत घोषित करने की तैयारी

काठमांडू

नेपाल सरकार विनाशकारी बाढ़ में लापता लोगों के तीन महीने तक नहीं मिलने पर उन्हें मृत घोषित कर मृत्यु पंजीकरण करने की तैयारी कर रही है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता और डीआईजी अविनारायण काफ्ले के अनुसार, बाढ़ के बाद अब भी 4,655 लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। सरकार ने विपद् संबंधी कुछ नेपाल ऐन को संशोधन करने संबंधी ऐन, 2083 के जरिए इस संबंध में कानूनी व्यवस्था करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। प्रस्तावित कानून तत्काल लागू होने की बात कही गई है। इसके तहत गंभीर प्रकृति की आपदाओं के प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 2074 में संशोधन कर धारा 33 (क) जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें गंभीर आपदा में मारे गए लोगों के शवों की तलाश, संरक्षण और परिवार को सौंपने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रावधान होगा।

1,436 शव मिले, 1,292 की पहचान नहीं – 1,436 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 1,292 शवों की पहचान नहीं हो सकी है और उन्हें दफना दिया गया है। शवों के डीएनए परीक्षण के जरिए पहचान होने पर उन्हें संबंधित परिवारों को सौंपने की व्यवस्था की गई है। पहचान न हो पाने वाले शवों को अलग-अलग बैग में पैक कर उनके विवरण के साथ सुरक्षित रखा गया है। पहचान होने के बाद संबंधित परिजन दफन किए गए शव को ले जा सकेंगे। अब तक 1,286 शवों और 1,997 परिजनों के डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। डीआईजी काफ्ले के अनुसार, अब तक एकत्र किए गए लगभग आधे नमूनों की रिपोर्ट भी आ चुकी है। सरकार के प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि यदि आपदा के बाद तीन महीने तक तलाश के बावजूद कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसे मृत मानते हुए मृत्यु पंजीकरण किया जा सकेगा। लापता लोगों के परिवारों को मिलने वाली राहत के संबंध में भी कानून में स्पष्ट व्यवस्था की जा रही है। तीन महीने बाद उन्हें भी अन्य मृतकों के परिवारों के समान सरकारी राहत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा। भोटेकोशी क्षेत्र को सरकार ने तीन महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस अवधि में खोज और बचाव अभियान जारी रहेगा। इसके बाद भी यदि लापता व्यक्ति नहीं मिलता है तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उसका मृत्यु पंजीकरण किया जा सकेगा। प्रस्तावित संशोधन में राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन में भी बदलाव किया जाएगा। बाढ़ में कुछ परिवारों के सभी सदस्य लापता होने के कारण मृत्यु पंजीकरण की सूचना कौन देगा, इसके लिए नई व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि लापता व्यक्ति का कोई संरक्षक या हकदार नहीं है तो स्थानीय तह के प्रमुख या संबंधित वार्ड अध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी को आधिकारिक माना जाएगा। विदेशी नागरिकों के मामले में नेपाल स्थित या नेपाल के लिए मान्यता प्राप्त संबंधित देश का दूतावास अथवा राजनयिक मिशन सूचना दे सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, आपदा के बाद लापता व्यक्ति की तलाश के बावजूद उसके नहीं मिलने पर उसके स्थायी पते या घटना घटित होने वाले स्थानीय तह के पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में मृत्यु पंजीकरण की सूचना दी जा सकेगी।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका ग्रीनलैंड में दो नए सैन्य ठिकाने बनाएगा, आर्कटिक में अमेरिकी का बढ़ेगी मौजूदगी

वाशिंगटन। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। न्यूयार्क में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच एक समझौते पर सहमति बनी है, जिसमें ग्रीनलैंड में दो जगहों पर अमेरिकी मिलिट्री बेस स्थापित करने की योजना शामिल है। इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। इस योजना के तहत दक्षिणी ग्रीनलैंड के नरसार्सुआक में शीत युद्ध के दौर के पुराने अमेरिकी मिलिट्री बेस को दोबारा शुरू किया जा सकता है। यह बेस, जिसे तब ब्लू वेस्ट वन के नाम से जाना जाता था, अमेरिका ने 1950 के दशक में बंद कर दिया था। इसके बाद इस इलाके की आबादी घटकर कुछ दर्जन लोगों तक रह गई थी। वहीं, पूर्वी ग्रीनलैंड के मेस्टर्सविग में एक दूसरा सैन्य ठिकाना बनाया जा सकता है। मेस्टर्सविग में फिलहाल डेनमार्क की स्पेशल फोर्स की सिरियस डाग स्लेज पेट्रोल यूनिट काम करती है। हालांकि, समझौते का पूरा टेक्स्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, कुछ विवरणों को हस्ताक्षर होने तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि यह समझौता ग्रीनलैंड और अमेरिका की सुरक्षा को सुरक्षित करने और मजबूत करने में मदद करेगा। डेनमार्क का भी कहना है कि इस समझौते से आर्कटिक की सुरक्षा नाटो के दायरे में आएगी, और यह केवल अमेरिका और डेनमार्क की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर लंबे समय से जारी कोशिशों के बीच हो रहा है। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहिए, और उन्होंने इसे हासिल करने के लिए सैन्य या आर्थिक ताकत के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया था। ट्रंप के इन बयानों के बाद नाटो के भीतर भी कूटनीतिक तनाव बढ़ा था, जिसके बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की।

नेपाल ने पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी से सहयोग मांगा

काठमांडू। नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने हाल में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी से सहयोग मांगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जर्मनी की आर्थिक सहयोग एवं विकासमंत्री रिम अलाबाली राडोवान के साथ द्विपक्षीय साइडलाइन बैठक में मंत्री खनाल ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण के साथ-साथ जलवायु-लचीलेपन, आपदा पूर्व तैयारी और क्षमता विकास में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेशमंत्री खनाल ने नेपाल की विकास प्रक्रिया में जर्मनी की ओर से लंबे समय से दिए जा रहे महत्वपूर्ण सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। राडोवान ने नेपाल में हाल में आई विनाशकारी आपदा को वैश्विक साझा चुनौती बताते हुए कहा कि जर्मनी नेपाल को वित्तीय और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईरान की पड़ोसी देशों को चेतावनी, अमेरिकी प्रतिबंधों में सहयोग पर मार्ग प्रभावित करने की धमकी

तेहरान। अमेरिका की ओर से ईरानी एयरलाइंस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा के बीच ईरान ने पड़ोसी देशों को इन पाबंदियों को लागू करने में सहयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में सहयोग करने वाले देशों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के अर्ध-सरकारी स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क (एसएनएन) को दिए एक साक्षात्कार में रेजाई ने पड़ोसी देशों से अमेरिकी कदमों में शामिल होने से बचने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी वाणिज्यिक उड़ानों, यात्री सेवाओं और माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग न करने को कहा। रेजाई के मुताबिक, यदि क्षेत्र के देश ईरान के हवाई परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने में सहयोग करते हैं, तो जवाब में उन देशों के हवाई अड्डों और विमानन मार्गों को भी बंद करने या बाधित करने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने अमेरिका के साथ भविष्य में संभावित बातचीत को लेकर भी सख्त रुख का संकेत दिया। रेजाई ने कहा कि वाशिंगटन के साथ आगे की वार्ता और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने जैसे मुद्दे ईरान की शर्तों पर निर्भर होंगे।

जलवायु आपदा से उबरने के लिए नेपाल को दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी : विदेशमंत्री शिशिर खनाल

काठमांडू

नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने जलवायुजनित आपदाओं से प्रभावित नेपाल में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर आयोजित जी-7 विकास मंत्रीस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए खनाल ने नेपाल में हाल की जलवायुजनित आपदा की स्थिति का उल्लेख किया और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पीड़ितों के पुनर्वास, जलवायु वित्त, आपदा पूर्व तैयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग और हिमालयी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर जी-7 के सहयोग और साझेदारी का आह्वान किया।

नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए खनाल ने जलवायु आपदा की कठिन परिस्थितियों में नेपाल के प्रति एकजुटता और सहयोग के लिए जी-7 सदस्य देशों तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के प्रति नेपाल सरकार और नेपाली जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, नेपाल जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, लचीलापन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में जी-7 के नेतृत्व की उच्च सराहना करता है। उन्होंने बैठक के आयोजन के लिए जी-7 की अध्यक्षता कर रहे फ्रांस को भी धन्यवाद दिया।

पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डालर से अधिक की जरूरत – मंत्री खनाल ने कहा कि हाल की जलवायुजनित आपदा से नेपाल में मानवीय और भौतिक क्षति बेहद व्यापक हुई है। बाढ़ से घरों, सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों और जलविद्युत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इससे जनजीवन के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब अमेरिकी डालर से अधिक की आवश्यकता होगी। आपदा के वैज्ञानिक अध्ययन का काम जारी होने की जानकारी देते हुए खनाल ने कहा कि शुरुआती विवरणों के अनुसार तेजी से गर्म हो रहे हिमालयी वातावरण में बर्फ, चट्टान, पानी और अस्थिर भू-आकृतियों के बीच जटिल अंत:क्रिया के कारण यह आपदा उत्पन्न हुई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका विस्तृत अध्ययन अभी जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ भूगर्भीय, हिमनदीय और जलविज्ञान संबंधी कारणों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

जलवायु परिवर्तन अब दूर का खतरा नहीं – खनाल ने कहा, जलवायु परिवर्तन नेपाल के लिए अब दूर का खतरा नहीं है। यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है और इसके प्रभाव की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जनधन और आजीविका को नुकसान पहुंचने के साथ लंबे प्रयासों से हासिल विकास की उपलब्धियां भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय, नदियां, समुदाय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे बाढ़, भूस्खलन, हिमनदीय जोखिम तथा अन्य जलवायुजनित आपदाओं के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं।

खनाल ने कहा कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल का योगदान बेहद कम है, लेकिन इसके बावजूद देश को जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नेपाल को और अधिक सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा, नेपाल का वैश्विक उत्सर्जन में योगदान बेहद कम है। लेकिन विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से लेकर हिमनदों के पिघलने तक के जलवायुजनित प्रभावों को हम असमान रूप से झेल रहे हैं।

नेपाल की पांच प्रमुख अपेक्षाएं – पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल की पांच प्रमुख अपेक्षाएं सामने रखते हुए खनाल ने सबसे पहले पुनर्वास के लिए साझेदारी की आवश्यकता बताई।

मानवीय सहायता के लिए मित्र देशों से मिले सहयोग और सद्भावना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अनुदान तथा रियायती वित्तीय संसाधनों सहित समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं।

दूसरी प्राथमिकता के रूप में उन्होंने जलवायु वित्त तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि और क्षति के लिए वित्तीय सहायता विकासशील और जलवायु जोखिम वाले देशों को तेज, सरल और सहज तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नेपाल ने हानि और क्षति कोष से संबंधित वित्तीय व्यवस्था के लिए अनुरोध किया है और अब सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है।

आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश बढ़ाने की अपील – खनाल ने आपदा रोकथाम और पूर्व तैयारी में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने पूर्व चेतावनी प्रणाली, जलवायु संबंधी जानकारी, जल एवं मौसम सेवाओं, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे तथा समुदाय आधारित आपदा पूर्व तैयारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने जी-7 और अन्य साझेदार देशों से जलवायुजनित आपदाओं की बढ़ती गंभीरता से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से तेजी से, कम लागत पर और आसानी से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

खनाल ने कहा, समय पर उपलब्ध वित्तीय संसाधन केवल एक वित्तीय साधन नहीं, बल्कि जलवायुजनित झटकों से बार-बार प्रभावित होने वाले जोखिमग्रस्त देशों के लिए जीवनरेखा हैं। उन्होंने जी-7 सदस्य देशों से बहुपक्षीय विकास बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में अपने प्रभाव और समन्वय क्षमता का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। हिमालय को वैश्विक जलवायु एजेंडे में प्राथमिकता देने की मांग खनाल ने हिमालयी क्षेत्र को वैश्विक जलवायु एजेंडे में अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रपति ट्रंप और ताकाइची ने जापान-अमेरिका गठबंधन की मजबूती को सराहा

न्यूयार्क

दोनों ने बैठक में मजबूत और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर दिया बल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापानी पीएम सनाए ताकाइची ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र एक अहम बैठक में अपने देशों के गठबंधन की अटूट मजबूती और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बल दिया। ट्रंप ने इस द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत ताकाइची की जमकर तारीफ करते हुए की, उन्हें अपना दोस्त बताया और कहा कि उन्हें जापान के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनके आंकड़ों पर हमेशा नजर रखता हूं और जापान का उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ताकाइची के साथ होना सम्मान की बात है और वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगी। ट्रंप ने ताकाइची के साथ आए जापानी अधिकारियों की भी सराहना की, उन्हें मजबूत और समझदार बताया। ताकाइची ने एक अनुवादक के जरिए ट्रंप का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशिया सहित वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के मौजूदा दौर में ट्रंप ने दोनों देशों की साझेदारी के लिए अत्यंत मजबूत प्रतिबद्धता प्रदान की है। ताकाइची ने कहा कि न्यूयार्क में इस बैठक का मकसद दुनिया को यह एक सशक्त संदेश देना था कि उनका गठबंधन कितना सुदृढ़ है। ताकाइची ने हाल ही में हुए अपने कैबिनेट फेरबदल के बारे में भी ट्रंप को अवगत कराया, जिसमें उनकी सरकार के 18 में से 10 नए मंत्री नियुक्त किए गए थे। हालांकि, उन्होंने रेखांकित किया कि विदेश नीति, वित्त, आर्थिक मामलों और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख अपने पदों पर बने रहे। ताकाइची ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतरता अमेरिका में उनके समकक्षों के साथ सीधे कामकाजी रिश्ते बनाए रखने और वाशिंगटन तथा टोक्यो के बीच नीतिगत तालमेल को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच गठबंधन और मजबूत होगा। पीएम ताकाइची ने आर्थिक सुरक्षा को दोनों देशों के संबंधों का एक और विस्तृत होता दायरा बताया।

नेपाल : लैंडिंग के दौरान सीता एयर के विमान का पिछला पहिया निकला, बड़ा हादसा टला

काठमांडू। नेपालगंज से डोल्पा के लिए उड़ान भरने वाले सीता एयर के विमान का डोल्पा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पिछला पहिया निकल गया। हालांकि, विमान बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। जिला पुलिस कार्यालय डोल्पा के अनुसार, डोल्पा के जुफाल एयरपोर्ट पर अवतरण के दौरान विमान का पिछला पहिया निकल गया। जिला पुलिस कार्यालय डोल्पा के प्रमुख पुलिस उपरीक्षक अनिल राज गिरी ने बताया कि सीता एयर का 9एन-एजेएच विमान सुबह करीब 8:25 बजे जुफाल एयरपोर्ट पर उतर रहा था, तभी उसका पिछला पहिया निकल गया। गिरी के अनुसार, पहिया निकलने के बावजूद विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया और बड़ा हादसा टल गया।

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के रोहिंग्या मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचा

न्यूयार्क

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने देश के रोहिंग्या मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर रोहिंग्या संकट: लंबे समय तक विस्थापन से न्याय और जवाबदेही के साथ टिकाऊ समाधान के लिए एक नई अपील विषयक सम्मेलन में विचार रखे। उन्होंने पांच सूत्रीय प्रस्ताव रखते हुए रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजने का भरोसेमंद रोडमैप बनाने की अपील की।

बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, तारिक रहमान ने कहा कि अब विस्थापन को खत्म करने की ओर बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि सहानुभूति से असली कारणों और उनके समाधानों की तलाश की जाए। भरोसेमंद कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव बांग्लादेश में शरण लिए हुए 1.2 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्याओं की बुरी हालत पर रोशनी डालते हुए दिया। तारिक विश्व समुदाय से उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए हालात बनाने के लिए पक्के इरादे के साथ अपनी जिम्मेदारी उठाने की अपील की।

उन्होंने कहा, बांग्लादेश नहीं चाहता कि रोहिंग्या हमेशा के लिए बेघर रहें। हम चाहते हैं कि वे म्यांमार में अपने घरों में सुरक्षित, अपनी मर्जी से, सम्मान के साथ और अपने अधिकारों की रक्षा के साथ लौटें। तारिक ने आगे कहा, बांग्लादेश ने इंसानियत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर जरूरी हालात बनते हैं तो बांग्लादेश उनकी वापसी में मदद करने के लिए तैयार रहेगा। इस सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश और गाम्बिया ने संयुक्त रूप से किया। इसमें अलग-अलग देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

उन्होंने म्यांमार में रोहिंग्याओं समेत आम लोगों के खिलाफ हिंसा खत्म करने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि वापसी के लिए भरोसा वापस पाने के लिए उनके अपने देश में उनके बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। रोहिंग्याओं की लगातार वापसी पक्का करने के लिए न्याय और जवाबदेही जरूरी है, साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के सामने जवाबदेही तय करने में गाम्बिया की भूमिका की तारीफ की। तारिक ने रोहिंग्या संकट को म्यांमार से शुरू हुआ बताते हुए कहा, यह संकट म्यांमार से शुरू हुआ। इसका हल म्यांमार में है। उन्होंने कहा कि रखाइन राज्य में हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। वहां रोहिंग्याओं को गंभीर उल्लंघन और बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, म्यांमार मिलिट्री और अराकान आर्मी दोनों ने गंभीर उल्लंघन किए हैं। ऐसे में, सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के हालात मुश्किल बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री तारिक ने कहा कि बांग्लादेश नौ साल से ज्यादा समय से रोहिंग्याओं को होस्ट कर रहा है। लगभग 6,000 लर्निंग सेंटर के जरिए म्यांमार के करिकुलम के आधार पर खाना, हेल्थकेयर और शिक्षा दे रहा है। इसके अलावा रोहिंग्या युवाओं को कैपेसिटी-बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दे रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि, इंसानी उदारता राजनीतिक निष्क्रियता का बहाना नहीं बन सकती। बांग्लादेश से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हमेशा यह जिम्मेदारी उठाएगा। रहमान ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक विस्थापन से नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जिनमें मानव तस्करी, प्रवासियों की तस्करी, ड्रग तस्करी और दूसरे अंतरराष्ट्रीय अपराध शामिल हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप की एक ही शर्त, ईरान को शांति समझौता चाहिए तो पहले परमाणु कार्यक्रम छोड़ेः रुबियो

न्यूयार्क

अमेरिका के सेक्रेटरी आफ स्टेट (विदेशमंत्री) मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान से अगर समझौता होता है तो उसे हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं। मगर एक शर्त के साथ। वह शर्त है ईरान को परमाणु हथियारों का मोह त्यागना होगा। तब समझौता होगा और ईरान फिर महान देश बन सकेगा। उन्होंने 23 सितंबर को न्यूयार्क के आलीशान पैलेस होटल में खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के ईरान मुद्दे के अलावा अन्य सवालों के सौहार्दपूर्ण माहौल में जवाब दिए। यूएस डिपार्टमेंट आफ स्टेट (विदेश मंत्रालय) की वेबसाइट ने सवाल-जवाब के अलावा संवाददाता सम्मेलन का वीडियो साझा किया है।

संवाददाता सम्मेलन में पहुंचते ही रुबियो ने कहा कि ठीक है, आगे बढ़िए। उनसे पहला सवाल ईरान पर पूछा गया- कल ईरानियों के साथ अमेरिका की क्या मांगें थीं और क्या समझौता (एमओयू) में लौटने पर कोई चर्चा हुई या अमेरिका के लिए शर्तें बदल गई हैं विदेशमंत्री रुबियो ने कहा, देखिए, कल की बातचीत उस प्रक्रिया में शामिल कुछ मध्यस्थों के साथ हुई। मैं इसे किसी एक दिशा में नहीं बताना चाहता। मुझे लगता है कि इसकी समझ बिल्कुल साफ है। याद रखिए, यहां सबसे मुख्य मुद्दा - जिसे राष्ट्रपति ने कल दुनिया के सामने अपने भाषण में जोर देकर कहा - वह यह है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। सब कुछ इसी बात से जुड़ा है।

उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक मुद्दा है। जलडमरूमध्य का दक्षिणी रास्ता खुला है। हर दिन वहां से ज्यादा से ज्यादा तेल के बैरल गुजर रहे हैं। यह रास्ता अमेरिकी सेना की कोशिश की वजह से खुला है। अमेरिकी सेना जहाजों की सुरक्षा भी कर रही है और उसने बारूदी सुरंगें (माइंस) भी हटाई हैं। और यह सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच, होर्मुज

जलडमरूमध्य में एकमात्र नाकाबंदी वह है जो हमने ईरान पर लगाई है, क्योंकि तेहरान जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। उसने ऐसा ही किया। अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी मुद्दा है।

रुबियो ने कहा, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। हम हर बातचीत में यह बात रखते हैं। मैं इन बैठकों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर ईरान के साथ कोई समझौता होता है तो वह प्रेस कान्फ्रेंस में नहीं होगा। इसमें लंबा समय लगेगा। इस प्रक्रिया में मध्यस्थ भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने कहा है कि वे समझौते के लिए तैयार हैं, जिससे ईरान महान और समृद्ध देश बन सके। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार पाने की अपनी इच्छा पर अड़ा रहता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला देश है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास कई विकल्प हैं। सैन्य विकल्प भी है। उसके बारे में मैं कोई अंदाजा नहीं लगाऊंगा।

अमेरिकी विदेशमंत्री ने क्यूबा के आजादी के सवाल पर कहा, हां वह आजाद होगा। इस पर कई पूरक सवाल पूछे गए। रुबियो ने कहा, क्यूबा की क्रांति - मैं जवाब देना चाहता हूं। क्यूबा की क्रांति नाकाम रही है। सवाल यह है कि अब क्या होगा। मुझे लगता है कि क्यूबा के पास बदलाव करने का मौका है।इसमें राजनीतिक और आर्थिक आजादी दोनों ही शामिल हैं। हम आगे ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिनसे बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। हमने दुनिया भर में इतिहास में ऐसे बदलाव होते देखे हैं। वे रातों-रात नहीं होते। कोई भी 60 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अक्षमता को छह महीने में ठीक नहीं कर सकता।

उनसे यह पूछा गया कि क्या क्यूबा में वेनेजुएला जैसा कुछ हो सकता हैरुबियो ने कहा, अमेरिका पहले है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को क्यूबा से कोई खतरा होता है तो राष्ट्रपति के पास उससे निपटने की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों होती हैं। मैं इससे आगे कोई अनुमान नहीं लगाऊंगा।

मैं बस इतना कहूंगा कि क्यूबा और उसके नेताओं या जो लोग अभी सरकार चला रहे हैं, उनके पास उस देश को हमेशा के लिए सकारात्मक रूप से बदलने की प्रक्रिया शुरू करने का मौका है। क्यूबा की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम कभी काम नहीं कर सकते ,क्योंकि उनके हाथ खून से सने हैं।